

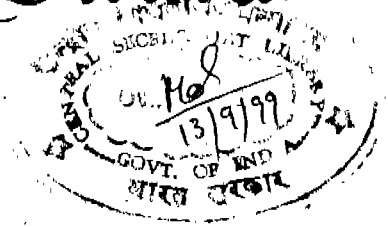


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 47]
No. 47]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 1999/ज्येष्ठ 7, 1921
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 1999/JYAISTHA 7, 1921

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 28 मई, 1999

सं० 311-1/99-टी आर ए आई/इकोन.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावकारी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त अपने-अपने राजस्व की भागीदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है।

दूरसंचार अंतःसंयोजन (इंटरकनेक्शन)
(प्रभार एवं राजस्व भागीदारी) विनियम, 1999
(1999 का 1)

खंड I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

- इस विनियम का नाम "दूरसंचार अंतःसंयोजन (प्रभार एवं राजस्व भागीदारी) विनियम, 1999" होगा।
- इस विनियम में सेवा प्रदाताओं के बीच समूचे भारतीय क्षेत्र में तथा भारत से शुरू होकर विदेश में समाप्त होने वाली सभी दूरसंचार सेवाओं के अंतःसंयोजन एवं राजस्व भागीदारी के लिए व्यवस्थाएं शामिल होंगी।
- यह विनियम मई 1, 1999 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

खंड II

परिभाषाएं

2. इस विनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 अभिप्रेत है।
- "प्राधिकरण" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है।

- (iii) "बुनियादी दूरसंचार सेवाएं" से पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क (पी एस टी एन) से प्राप्त सेवाएं अभिप्रेत हैं।
- (iv) "उच्चतम (i)" से समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा निर्दिष्ट दूरसंचार सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन प्रभार की उच्चतम सीमा (सीमाएं) अभिप्रेत हैं।
- (v) "स्वदेशी लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा" अथवा डी एल डी का तात्पर्य किसी एक सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के स्थानीय क्षेत्र को भारत की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए अपेक्षित दूरसंचार सेवाओं से है ताकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के आर-पार वायस और नॉन वायस सिग्नल के प्रेषण की अनुमति दी जा सके।
- (vi) "फ्लोर" का तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट दूरसंचार सेवाओं के लिए अंतःसंयोजन प्रभार की उस न्यूनतम सीमा से है जिससे नीचे ऐसे प्रभार प्रस्तुत किए जाएं।
- (vii) "स्थगन" इस बात को इंगित करता है कि प्राधिकरण ने, फिलहाल, किसी विशेष दूरसंचार सेवा के लिए कोई अंतःसंयोजन प्रभार राजस्व भागीदारी व्यवस्था अधिसूचित नहीं की है और सेवा प्रदाता ऐसी सेवा के लिए कोई भी प्रभार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।
- (viii) "अंतःसंयोजन" से वे वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्थाएं अभिप्रेत हैं जिसके तहत सेवा प्रदाता दूसरे सेवा प्रदाताओं के ग्राहकों, सेवाओं और नेटवर्कों से संपर्क स्थापित करने के लिए अपने उपस्कर, नेटवर्क तथा सेवाओं को जोड़ देते हैं ताकि उनके ग्राहकों का उनसे संपर्क बन जाए।
- (ix) "अंतःसंयोजन प्रभार" से वह प्रभार अभिप्रेत है जो अंतःसंयोजन के लिए एक अंतःसंयोजन प्रदाता द्वारा अंतःसंयोजन लेने वाले से वसूल किया जाता है।
- (x) "अंतःसंयोजन प्रदाता" से वह सेवा प्रदाता अभिप्रेत है जिसके नेटवर्क से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अंतःसंयोजन लिया जाता है।
- (xi) "अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता" से वह सेवा प्रदाता अभिप्रेत है जो अंतःसंयोजन प्रदाता के नेटवर्क से अंतःसंयोजन लेता है।
- (xii) "अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवा" से वे दूरसंचार सेवाएं अभिप्रेत हैं जो भारत के भीतर सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के स्थानीय क्षेत्र को दूसरे देश के सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के स्थानीय क्षेत्र से जोड़ने के लिए अपेक्षित होती हैं ताकि वायस और नॉन वायस सिग्नलों के संप्रेषण की अनुमति दी जा सके।
- (xiii) "अन्तर्राष्ट्रीय अपभोक्ता डायलिंग" अथवा आई एस डी से सार्वजनिक नेटवर्क के जरिए सीधे डायल करके भारत के एंड यूजर का दूसरे देश के एंड यूजर के बीच सीधा अंतःसंयोजन अभिप्रेत है।
- (xiv) "पट्टाशुदा सर्किट" से उपभोक्ताओं अथवा सेवा प्रदाताओं को पट्टे (लीज) पर दी गई दूरसंचार सुविधाएं अभिप्रेत हैं जिससे उन नेटवर्क टर्मिनेशन प्वाइंटों जिन्हें प्रयोक्ता पट्टाशुदा सर्किट व्यवस्था के भाग के रूप में तथा जिनमें पट्टाशुदा सर्किट बैंडविड्थ के लचीले प्रयोग वाली प्रणालियां भी शामिल की जा सकती हैं, के बीच टेक्नालॉजी पारदर्शी संचारण क्षमता प्रदान की जा सके।
- (xv) "अंतःसंयोजन प्रभार में पक्षपात न करना" का तात्पर्य यह है कि सेवा प्रदाता अंतःसंयोजन प्रभारों के मामले में सेवा प्रदाताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें पर्याप्त लागत भेद का आधार शामिल नहीं है और वह भी ऐसे लागत भेद द्वारा औचित्य सिद्ध सीमा तक ही होगा।
- (xvi) "आदेश" के दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 अभिप्रेत है।
- (xvii) "प्रारंभिक नेटवर्क" से वह नेटवर्क अभिप्रेत है जिससे एक दूरसंचार सन्देश के प्रवर्तक को सीधे जोड़ दिया जाता है।
- (xviii) "प्रारंभिक/ट्रांजिट/टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाता" से वह सेवा प्रदाता अभिप्रेत है जिसका नेटवर्क दूरसंचार सन्देश को प्रारंभ करने/ट्रांजिट/टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- (xix) "पत्तन या पोर्ट प्रभार" से वह प्रभार अभिप्रेत है जो अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता द्वारा अंतःसंयोजन प्रदाता के नेटवर्क इंटरफेस पर अंतःसंयोजन लिंकों को टर्मिनेट करने के लिए अंतःसंयोजन प्रदाता को देना होता है।
- (xx) "विनियम" से दूरसंचार अंतःसंयोजन (प्रभार एवं राजस्व भागीदारी) विनियम, 1999 अभिप्रेत है।
- (xxi) "रिपोर्ट करने संबंधी शर्त" का तात्पर्य सेवा प्रदाता की उस बाध्यता से है जिसके अनुसार उसे इस नियम तथा बाद में हुए किसी परिवर्तन के तहत दूरसंचार सेवाओं के लिए किसी नए अंतःसंयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी की व्यवस्था लागू करने से 45 दिन पहले प्राधिकरण को रिपोर्ट देनी होती है।
- (xxii) "अंतःसंयोजन की लागत नियत करना" से किसी इंजीनियरी कार्य की वह प्रारंभिक लागत अभिप्रेत है जिसकी प्रार्थित अंतःसंयोजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए जरूरत होती है।

- (xxiii) "उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग" अथवा एस टी डी का तात्पर्य है सार्वजनिक नेटवर्क के जरिए सीधी डायलिंग करके भारत के भीतर दो उपभोक्ताओं के बीच सीधा अंतःसंयोजन।
- (xxiv) "टर्मिनेटिंग नेटवर्क" से वह नेटवर्क अभिप्रेत है जिससे दूरसंचार सन्देश का रिसीवर सीधे जोड़ दिया जाता है।
- (xxv) "ट्रांजिट नेटवर्क" से वह नेटवर्क अभिप्रेत है जिसके जरिए प्रारंभिक नेटवर्कों अथवा अन्य ट्रांजिट नेटवर्कों से दूरसंचार सन्देश भेजे जाते हैं और प्रारंभिक अथवा अन्य ट्रांजिट नेटवर्कों को पहुंचा दिए जाते हैं।
- (xxvi) "उपभोग प्रभार" से वह प्रभार अभिप्रेत है जिसे कोई सेवा प्रदाता द्वारा अपने नेटवर्क से दूरसंचार सन्देश भेजने/विवरण करने/एकत्र करने के लिए लिया जाता है।
- (xxvii) इस नियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में है।

खंड III

3. अंतःसंयोजन प्रभार (इंटरकनेक्शन चार्ज) :

- (i) इस विनियम में जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लिखित न हो, अंतःसंयोजन प्रभार लागत पर आधारित होंगे।
- (ii) लागत आधारित अंतःसंयोजन प्रभारों के निर्धारण के लिए, मुख्य आधार "संवृद्ध अथवा अतिरिक्त" लागत होगा जो अंतःसंयोजन प्रदाता द्वारा अंतःसंयोजन की व्यवस्था करने के लिए सीधे प्रदान किया जाता है।
- (iii) कोई भी सेवा प्रदाता अंतःसंयोजन के प्रभार वसूल करने में सेवा प्रदाताओं के बीच भेदभाव नहीं करेगा।
ऐसी व्यवस्था है कि विशेष अंतःसंयोजन सुविधा प्रदान करने के लिए उठाई गई लागत में पर्याप्त अंतर का औचित्य सिद्ध होने पर भिन्न प्रभार वसूल किया जाए।
- (iv) कोई सेवा प्रदाता ऐसी अंतःसंयोजन सुविधा का प्रभार वसूल न करे जो मांगी न गई हो।
यदि अंतःसंयोजन सुविधा उसके प्राप्तकर्ता द्वारा मांगने अथवा अपेक्षित होने के रूप में प्रदान नहीं की जा सकती है, तो इस मामले पर अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता और प्रदाता के बीच आपसी सहमति पर निर्णय ले लिया जाए। यदि ऐसी सहमति संभव न हो, तो निर्णय के लिए मामले को प्राधिकरण को भेज दिया जाए। अंतःसंयोजन प्रदाता, अंतःसंयोजन सुविधा प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता को इस बात की सूचना देगा कि सुविधा अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता द्वारा मांगी गई अथवा अपेक्षित रूप में प्रदान की जा सकती है या नहीं।
- (v) अंतःसंयोजन प्रदान करने के लिए प्रयुक्त नेटवर्क के कुछ घटकों के प्रभार इस नियम की अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। पट्टाशुदा सर्किटों और इंटरनेट पोर्ट प्रभारों के बारे में अंतःसंयोजन प्रभार वही होंगे जो क्रमशः दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची IV और VI में निर्दिष्ट हैं।
- (vi) जब तक विशेष रूप से व्यवस्था न की गई हो, प्राधिकरण अंतःसंयोजन से संबंधित मामले से अलग है।
- (vii) जहां प्राधिकरण कुछ समय के लिए, अंतःसंयोजन प्रभार निर्दिष्ट करने से स्वयं को अलग रखे, तो ऐसे प्रभारों पर अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता और प्रदाता आपसी सहमति से निर्णय लेंगे।
- (viii) अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता और प्रदाता के बीच अंतःसंयोजन प्रभारों के बारे में आपसी सहमति इस खंड में प्रतिपादित सिद्धांतों पर आधारित होगी।
- (ix) जहां प्राधिकरण के हस्तक्षेप न करने वाले प्रभारों की प्रक्रिया शुरू करने के तीन महीने के भीतर अंतःसंयोजन प्रभार पर आपसी सहमति न हो पाए, तो प्राधिकरण मामले का निपटान करने के लिए अपनी ओर से अथवा किसी भी पक्ष के आवेदन करने पर हस्तक्षेप कर सकता है।

खंड IV

4. राजस्व भागीदारी व्यवस्था :

- (i) अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता और अंतःसंयोजन प्रदाता के बीच सेवा प्राप्त करने, जिसमें अंतःसंयोजन प्रदाता के नेटवर्क का उपयोग करना शामिल है, के लिए उपभोक्ता द्वारा अदा की जाने वाली जमा धनराशि में से राजस्व का बंटवारा किया जाएगा।
- (ii) जब तक कि इस नियम की अनुसूचियों में विशेष रूप से व्यवस्था न की गई हो, प्राधिकरण राजस्व भागीदारी व्यवस्था के मामले में स्वयं को दूर रखेगा।

- (iii) जहां प्राधिकरण, फिलहाल, किसी दूरसंचार सेवा अथवा उसके भाग के लिए राजस्व भागीदारी व्यवस्था निर्दिष्ट करने में स्वयं को दूर रखेगा, ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में सेवा प्रदाता आपसी सहमति में निर्णय लेंगे।
- (iv) जहां प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप न करने वाले प्रभारों की प्रक्रिया शुरू करने के तीन महीने के भीतर अंतःसंयोजन प्रभार पर आपसी सहमति न हो पाए, तो प्राधिकरण मामले निपटाने के लिए अपनी ओर से अथवा किसी भी एक पक्ष के आवेदन करने पर हस्तक्षेप कर सकता है।

खंड V

5. रिपोर्ट करने संबंधी शर्त :

- (i) सभी सेवा प्रदाता इस नियम के अधीन पहली बार निर्दिष्ट अंतःसंयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं तथा तत्पश्चात् हुए परिवर्तनों के संबंध में रिपोर्ट करने की शर्त का अनुपालन करेंगे। इसमें वह अंतःसंयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी की व्यवस्थाएं शामिल हैं जिन पर सेवा प्रदाताओं में पारस्परिक आधार पर निर्णय किया जाएगा।
- (ii) सेवा प्रदाता 45 कार्य दिवसों की अनिवार्य सूचना अवधि के बाद, प्रस्तावित अंतःसंयोजन प्रभारों एवं राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं को लागू कर सकता है बशर्ते कि प्राधिकरण ने इस अवधि के भीतर अन्यथा सीधे निर्देशन न दिया हो।
सिवाय इसके कि इस नियम के लागू हो जाने के पश्चात् पहली बार प्राधिकरण को रिपोर्ट दिए जाने के लिए अंतःसंयोजन प्रभार एवं राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं के लिए 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।
- (iii) जब कोई अंतःसंयोजन प्रदाता अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता को यह सूचित करता है कि वह उसके द्वारा मांगी गई अंतःसंयोजन सुविधा प्रदान नहीं कर सकता है, तो अंतःसंयोजन प्राप्तकर्ता इस प्रकार की सूचना मिलने के 45 दिनों के भीतर, प्राधिकरण से हस्तक्षेप का अनुरोध कर सकता है।
- (iv) कोई भी सेवा प्रदाता रिपोर्ट करने संबंधी शर्त का अनुपालन किए बिना अंतःसंयोजन प्रभार अथवा राजस्व भागीदारी व्यवस्था अथवा उसके किसी भाग में कोई हेर-फेर नहीं करेगा।

खंड VI

6. समीक्षा :

- (i) प्राधिकरण, समय-समय पर अंतःसंयोजन प्रभार और/अथवा राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन कर सकता है।
- (ii) प्राधिकरण, किसी समय भी, किसी प्रभावित पार्टी से संदर्भ प्राप्त होने अथवा पर्याप्त कारणों से किसी अंतःसंयोजन प्रभार अथवा राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के साथ-साथ उसमें संशोधन कर सकता है।

खंड VII

7. व्याख्यात्मक ज्ञापन :

इस विनियम में अनुलग्नक "क" दिया गया है जो इस विनियम में स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करने संबंधी मामलों पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के रूप में शामिल है।

खंड VIII

अवशिष्ट धाराएं

8. अतिप्राथमिक प्रभाव :

अंतःसंयोजन प्रभारों तथा राजस्व भागीदारी के संबंध में इस विनियम के प्रावधानों का किसी सेवा प्रदाता के लाइसेंस धारक के नियम एवं शर्तों के साथ-साथ किसी प्रारंभिक/ट्रांजिट/टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित शर्तों अथवा प्रभारों पर अतिप्राथमिक प्रभाव पड़ेगा।

9. व्याख्या :

इस विनियम के किसी प्रावधान की व्याख्या के बारे में विवाद उत्पन्न होने पर, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

हरपवर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

अनुसूची I

अंतः संयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी

मद	बुनियादी सेवाओं के लिए राजस्व भागीदारी
1	2
(1) लागू करने की तारीख	1 मई, 1999
(2) कवरेज	बुनियादी सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क से की जाने वाली कॉलें तथा दूसरे बुनियादी सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क में प्रेषित की जाने वाली तथा वहीं समाप्त हो जाने वाली कॉलें।
(3) स्थानीय कॉलें	प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए बिल बनाना और रखना
(4) घरेलू लंबी दूरी की कॉलें (एस टी डी कॉलें)	अपने नेटवर्क से कॉल शुरू/प्रेषित करने वाले सेवा प्रदाता को कॉल प्रेषित/समाप्त करने वाले सेल प्रदाताओं को, परियात के लिए अंतः संपर्क से लेकर कॉल समाप्त होने तक के अंतः संयोजन के समय पर मापी गई कॉल यूनिटों के लिए 0.48 प्रति यूनिट का भुगतान एस टी डी प्लस दर आधार पर करना होगा। बशर्ते ऐसे किसी प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा जहाँ अंतः संयोजन का प्वाइंट कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (SDCA) हो तथा यह कि ऐसा कोई प्रभार-भुगतान नहीं किया जाएगा जहाँ टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाता ने यह अनुरोध किया हो कि शुरू/प्रेषित करने वाले सेवा प्रदाता द्वारा कॉल गन्तव्य स्थान एस डी सी ए के बदले एस डी सी ए में सौंप दी जाए।
(5) अंतर्राष्ट्रीय कॉलें	कॉल शुरू करने वाला सेवा प्रदाता, ट्रांजिट सेवा प्रदाता (इस समय दूर संचार विभाग) को अंतः संयोजन के प्वाइंट पर मापी जाने वाली कॉल यूनिटों के लिए 0.66 प्रति यूनिट मापित कॉल का भुगतान करेगा।
टिप्पणियाँ :	
(क) "स्थानीय कॉलें" वे कॉलें कहलाती हैं जो एस डी सी ए में सेवाप्रदाता के नेटवर्क/एक्सचेंज के उपभोक्ताओं द्वारा की जाती हैं और निम्न स्थानों पर समाप्त होती हैं।	
(i) एक ही एस डी सी ए के निकटस्थ टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली में बशर्ते ये कॉलें केवल गन्तव्य स्थान एस डी सी ए में दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क में वितरित/सौंपी गई हों।	
(ख) घरेलू लंबी दूरी की कॉलों के लिए 0.48 प्रति मीटर की गई कॉल पर भुगतान के लिए कॉलों की यूनिटों की संख्या की गणना, अंतः संयोजन के प्वाइंट और गेटवे टेक्स, जहाँ तत्पश्चात् कॉल, केरिण्ड/टर्मिनेशन के लिए आगे वितरित की जाती हैं के बीच की अरीय (रेडियल) दूरी के एस टी डी टैरिफ प्लस पर आधारित होगी।	
(ग) पहले वाले नेटवर्क से की जाने वाली कॉलों के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता और सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता के बीच राजस्व बंटवारा नहीं किया जाएगा।	
(घ) विदेश संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के भारतीय और विदेशी संवाहकों के बीच राजस्व हिस्सेदारी प्रबंध अनुसूची नहीं भेजी जाएगी।	

अनुसूची II

अंतः संयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी

मद	सेल्यूलर मोबाइल के लिए राजस्व भागीदारी
1	2
(1) लागू करने की तारीख	1 मई, 1999
(2) कवरेज	सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क से की जाने वाली कॉलें तथा दूसरे बुनियादी सेवा प्रदाता के नेटवर्क में प्रेषित अथवा समाप्त होने वाली कॉलें।

1	2
(3) सेल्यूलर मोबाइल से बुनियादी सेवा उपभोक्ता को की जाने वाली स्थानीय कॉलें	बुनियादी सेवा प्रदाता को, प्लस दर पर मापी गई मीटरित कॉलों के अनुसार 1.20 प्रति मीटरित कॉल की दर पर किया जाने वाला भुगतान बुनियादी सेवा स्थानीय कॉल में लागू होगा।
(4) सेल्यूलर मोबाइल से बुनियादी सेवा उपभोक्ताओं को की जाने वाली घरेलू लंबी दूरी की कॉलें	बुनियादी सेवा प्रदाता को भुगतान घरेलू लंबी दूरी कॉलों में लागू दरों के आधार पर किया जाएगा। अंतः संयोजन से गन्तव्य स्थान तक समान एस टी डी के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा करवाई जाने वाली कॉल की दूरी के समान वसूलने योग्य दूरी सहित बुनियादी सेवा लंबी दूरी की कॉलों में लागू प्लस दर पर मापी गई मीटरित कॉलों की संख्या के अनुसार 1.20 प्रति मीटरित कॉल पर प्रभार वसूल किया जाएगा।
(5) सेल्यूलर मोबाइल से अंतर्राष्ट्रीय कॉलें	अंतर्राष्ट्रीय कॉलों में लागू दर पर बुनियादी सेवा प्रदाता को भुगतान/बुनियादी सेवा उपभोक्ता द्वारा की गई समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉल में लागू प्लस दर पर अंतः संयोजन के प्वाइंट पर मापी गई मीटरित कॉलों की संख्या सहित 1.20 रुपए प्रति मीटरित कॉल पर प्रभार वसूल किया जाएगा।
(6) सेल्यूलर मोबाइल से सेल्यूलर मोबाइल तक कॉलें	बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा अग्रेषित (आंशिक) स्थानीय/घरेलू लंबी दूरी कॉलों के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता को स्थानीय/घरेलू लंबी दूरी कॉल में लागू दर पर भुगतान किया जाना होगा उक्त मद 3/मद 4, अर्थात् स्थानीय/लंबी दूरी कॉलों के लिए बुनियादी सेवा में लागू प्लस दर तथा अंतः संपर्क से गन्तव्य स्थान तक समकक्ष एस टी डी कॉल के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा अग्रेषित कॉल की दूरी के समान वसूलने योग्य दूरी की लंबी दूरी की कॉलों के लिए 1.20 रुपए प्रति मीटरित कॉल, में विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर राशि की गणना की जाएगी।
टिप्पणियां :	
(क)	बुनियादी सेवा प्रदाताओं द्वारा अग्रेषित कॉलों के लिए राजस्व भागीदारी याने हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कॉलों की परिभाषा वही है जो अनुसूची 1 में टिप्पणी (क) में दी गई है।
(ख)	सेल्यूलर मोबाइल से बुनियादी सेवा उपभोक्ता तक घरेलू लंबी दूरी की कॉलों के लिए बुनियादी सेवा प्रदाता को देय राजस्व की राशि का निर्धारण करने के लिए मापी गई कॉलों की यूनिटों की संख्या की गणना बुनियादी सेवा प्रदाताओं के गेटवे TAX पर गन्तव्य स्थान कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस डी सी ए) (SDCA) तक मीटरित ऐसी कॉलों की संख्या के रूप में की जाएगी।
(ग)	बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा अग्रेषित सेल्यूलर मोबाइल से सेल्यूलर मोबाइल तक घरेलू लंबी दूरी की कॉलों के लिए 1.20 रुपए प्रति मीटरित कॉल पर बुनियादी सेवा प्रदाता को दी जाने वाले कॉल यूनिटों की संख्या की गणना, अंतः संयोजन के प्वाइंट पर गेटवे TAX, जहाँ आगे कैरिएज के लिए कॉल स्वीकृत की जाती है तथा सेवा प्रदाता का गेटवे TAX, जिसके नेटवर्क में तत्पश्चात् कॉल सौंप दी जाती है दोनों के बीच अरीय (रेडियल) दूरी के आधार पर की जाती है।
(घ)	सेल्यूलर मोबाइल से की जाने वाली कॉलों के लिए एक और दूसरे बुनियादी सेवा प्रदाता के बीच राजस्व बंटवारे की व्यवस्था का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है।
(ङ)	इस विनियम में किसी सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं की ओर से दूसरे सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं को की जाने वाली कॉलों के लिए सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के बीच किसी राजस्व हिस्सेदारी की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

अनुसूची III

अंतः संयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी

मद	पोर्ट प्रभार
1	2
(1) लागू करने की तारीख	1 मई, 1999
(2) कवरेज	सेवा प्रदाताओं (इंटरनेट के लिए पोर्ट प्रभारों के अतिरिक्त, जो दूरसंचार टैरिफ अधिनियम 1998 की अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट है) द्वारा दिए गए पोर्ट प्रभार।

1	2	3
(3) पोर्ट प्रभार	पी सी एम की संख्या	वार्षिक प्रभार (रुपयों की अधिकतम सीमा प्रति पोर्ट)
	—8 तक	—37,000
	—8 से अधिक और 32 तक	—16,000
	—32 से अधिक	— 9,000

अनुसूचक "क"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

क. प्रस्तावना

- यह विनियम उस परामर्श प्रक्रिया का परिणाम है जिसकी शुरुआत नवम्बर, 1997 में एक परामर्शी दस्तावेज जारी करके हुई जिसमें दूरसंचार दरों और अंतःसंयोजकता के वाणिज्यिक पहलुओं से संबंधित संकल्पना, सिद्धांतों तथा प्रणालियों का उल्लेख किया गया है। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, 9 सितम्बर, 1998 को जारी एक अन्य परामर्शी दस्तावेज में अंतःसंयोजन प्रभारों तथा राजस्व भागीदारी संबंधी कुछ विशेष प्रस्ताव रखे गए थे। इन प्रस्तावों पर भी विभिन्न सेवा प्रदाताओं तथा अन्य इच्छुक पार्टियों, जिनमें इस क्षेत्र में अनेकानेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल हैं, के साथ वृहत् और विस्तृत विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया रखी गई थी।
- अंतःसंयोजन संबंधी इन विनियमों के व्यापक ढांचे में वाणिज्यिक और अन्य दोनों ही पहलू शामिल हैं। इस विनियम में अंतःसंयोजन प्रभारों एवं राजस्व भागीदारी की ही बात कही गई है। दूसरे अनुपूरक, विनियमों तथा निर्देशों का उल्लेख प्राधिकरण द्वारा अन्यत्र किया जाएगा।
- मुख्य नियमों तथा इन विनियम की अनुसूचियों में स्पष्टता और पारदर्शिता लाना तथा प्राधिकरण द्वारा अपने दूर-संचार टैरिफ आदेश, 1999 में निर्दिष्ट कुछ अंतःसंयोजन प्रभारों, शुल्कों को संगत शुल्क के रूप में व्यक्त करना इस ज्ञापन का प्रयोजन है।
- अंतःसंयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी का निर्धारण करते समय भारत में दूरसंचार क्षेत्र में मौजूद स्थिति और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 में यथा प्रतिबिंबित इस क्षेत्र में भावी उदारीकरण दोनों का ही ध्यान में रखा जाए। नीति संबंधी इन परिवर्तनों के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय विकास तथा उनके लागत प्रभावों एवं कुछेक सेवाओं (अर्थात् बाजार के सेल्यूलर मोबाइल) क्षेत्र में कालिंग पार्टी द्वारा मूल अदायगी करने का सिद्धांत प्रारंभ करना) के लिए नई दर प्रणाली लागू करने से इस नियम में निर्दिष्ट अंतःसंयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी व्यवस्था के लागत के आधार में हेर-फेर हो सकता है।
- इस प्रकार इस विनियम में कुछ ऐसे घटक शामिल हैं जिनमें नेटवर्क संघटकों पर और अधिक विस्तृत डाटा विश्लेषण करके, समय के साथ-साथ परिवर्तन होता रहेगा। प्राधिकरण के दूसरे परामर्शी दस्तावेज (परामर्शी दस्तावेज सं. 98/3 दिनांक 9 सितम्बर, 1998) में ऐसी ही प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था जिसमें कहा गया है कि :
“दूरसंचार बाजार के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् पेटाशुद्ध लाइनों में प्रौद्योगिकीय और वाणिज्यिक विकास अंतःसंयोजन प्रभारों के निर्धारण के आधार को प्रभावित करता है। इन परिवर्तनों के अलावा, लागत पर अधिक विस्तृत और अद्यतन सूचना समय पर उपलब्ध हो जाएगी जो अंतःसंयोजन प्रभारों के लिए एक बेहतर मानसिक स्थिति प्रदान करेगा। अतः एक निश्चित समय पर अंतःसंयोजन प्रभारों की समीक्षा करनी आवश्यक होगी। अतः एक सामान्य सिद्धांतों के अलावा, अंतःसंयोजन मूल्यों की अंतरिम उपायों के रूप में पुनरीक्षा की जाए और फिर उसका समायोजन किया जाए (दूसरे परामर्शी दस्तावेज का अध्याय, VIII, पृष्ठ 44 देखें)।
- यह प्राधिकरण अभिगम्यता/कैरिज प्रभार व्यवस्था से संबंधित एक परामर्शी दस्तावेज तैयार कर रहा है। ये अभिगम्यता/कैरिज प्रभार हमारी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के 1999 में परिकल्पित बहुप्रचालकों द्वारा एक दूसरे को इंटरकनेक्शन करने के दूरसंचार वातावरण की अवस्था में एक कुशल इंटरकनेक्शन मुहैया करवाएगा।
- इस प्राधिकरण में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लेखों के पृथकीकरण से संबंधित एक परामर्शी दस्तावेज तैयार करने का भी कार्य चल रहा है। लेखों के पृथकीकरण का कार्य लागत आधारित अंतःसंयोजन प्रभार तथा राजस्व बंटवारे का निर्धारण करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। परंतु इसमें अधिक समय लगेगा। प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जा रहे अभिगम्यता/कैरिज प्रभार से संबंधित परामर्शी दस्तावेज में, निकट भविष्य में लेखों के पृथकीकरण से संबंधित कुछ पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। यदि आवश्यकता समझी गई तो भविष्य में की जाने वाली लेखा पृथकीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त विस्तृत जानकारी के बाद इसमें और सुधार कर लिया जाएगा।

ख. विनियम में प्रयुक्त कुछेक शब्दों की व्यापकता

- किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा किसी दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क के प्रयोग तथा कनेक्शन के लिए भुगतान को संकल्पनात्मक आधार पर निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है।

- संस्थापना लागत : अर्थात् प्रारंभिक रूप से दो नेटवर्कों को जोड़कर इस लिंक को प्रचालनात्मक बनाना (इसमें फाइबर लिंक, पोर्ट, भवन, किसी प्रकार के उपकरण का उन्नयन तथा लिंक को प्रचालनात्मक बनाने के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर शामिल हैं)।
- अंतः संयोजन प्रभार : यह प्रभार संस्थापना लागत के लिए भुगतान योग्य आवर्ती राशियां हैं।
- प्रयोग-प्रभार : यह वह भुगतान है जो अंतःसंयोजन चाहने वाले सेवा प्रदाता के उपभोक्ता द्वारा दूरसंचार संदेश के पारेषण के लिए नेटवर्क

के प्रयोग के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रभारों के भुगतान की पद्धति में अन्य चीजों के साथ-साथ राजस्व भागीदारी की व्यवस्था भी शामिल है।

ग. अंतः संयोजन प्रभार

(क) आधार

9. परामर्श-प्रक्रिया के दौरान उभर कर आने वाले मुख्य बिंदुओं में से एक यह था कि इन्टर कनेक्शन-मूल्य निर्धारण निम्न तरह होना चाहिए—
 - यह मुख्य रूप से उस वृद्धिकारी अथवा अतिरिक्त लागत पर आधारित होनी चाहिए जो इन्टरकनेक्शन की व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।
 - यह बिना भेदभाव के निर्धारित की जानी चाहिए।
10. इस विनियम में अंतःसंयोजन प्रभारों के निर्धारण के लिए ये सिद्धांत विनिर्दिष्ट किए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा अभिगम्यता/कैरिज प्रभारों के निर्धारण का कार्य करते समय भी ये सिद्धांत खासतौर पर परिलक्षित होंगे।

(ख) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अंतःसंयोजन प्रभार

11. इस प्राधिकरण ने तीन प्रकार के अंतःसंयोजन प्रभार विनिर्दिष्ट किए हैं, अर्थात्
 - पट्टे पर दिए गए सर्किट (दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची IV की भांति)
 - इंटरनेट के लिए पोर्ट प्रभार (दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की अनुसूची VI की भांति)
 - सेवा प्रदाताओं के एक्सचेंजों के लिए कनेक्शन हेतु पोर्ट प्रभार (इस विनियम की अनुसूची III), उपर्युक्त इंटरनेट के पोर्ट प्रभार के अतिरिक्त।
12. ये प्रभार मुख्य रूप से लागत पर आधारित हैं। जैसाकि द्वितीय परामर्शी दस्तावेज तथा इस विनियम में उल्लेख है कि इन प्रभारों की समय-समय पर समुचित समीक्षा की जाएगी।
13. पट्टे (लीज) पर दिए गए सर्किटों के अंतःसंयोजन प्रभार दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 का अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट पट्टे पर दिए गए सर्किटों की टैरिफ के समान है। यही (अर्थात् अंतःसंयोजन प्रभार के रूप में लागू टैरिफ) इंटरनेट पोर्ट प्रभार के लिए भी विधिमान्य है। इंटरनेट के पट्टे पर दिए गए सर्किटों का टैरिफ (पोर्ट प्रभार) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किया गया है।
14. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची VI में अंतर्राष्ट्रीय पट्टे पर दी गई लाइनों के टैरिफ के बारे में कोई जिक्र नहीं है क्योंकि यह टैरिफ उस अनुसूची के स्थगन के अधधीन है। यह अंतर्राष्ट्रीय पट्टाधीन लाइनों के अंतः संयोजन प्रभारों के लिए भी लागू होता है। प्राधिकरण द्वारा टैरिफ तथा अंतःसंयोजन प्रभार दोनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पट्टाधीन लाइनों की कीमत विनिर्दिष्ट करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण करने की योजना बना रहा है।
15. इस विनियम की अनुसूची III में सेवा प्रदाताओं द्वारा लिए जाने वाले पोर्ट प्रभारों को विनिर्दिष्ट किया गया है। परामर्श के दौरान पोर्ट प्रभारों के निर्धारण के लिए एक टिप्पणी यह भी सामने आई कि किसी भी अंतःसंयोजन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा की गई समय-समय पर पोर्टों की मांग संचयित होने की संभावना होनी चाहिए। इस संचयित मांग के लिए पोर्टों की पृथक-पृथक निजी रूप से मांग करने वालों की अपेक्षा प्रति पोर्ट, पोर्ट-प्रभार कम होगा। इसके विपरीत पोर्ट की आपूर्ति करने वालों की यह राय थी कि पोर्ट की प्रत्येक मांग पर अलग खर्च आता है, अतः इसके लिए अलग-अलग प्रभार लिए जाने चाहिए इन्हें पूर्व अथवा पश्चातवर्ती मांग के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
16. इस प्राधिकरण ने इन बिंदुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया है जिसमें अतिरिक्त पोर्ट प्रदान करने के लिए अतिरिक्त निवेश का मुद्दा भी शामिल है। प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस एक सरलीकृत प्रभारण की प्रक्रिया ही इस समस्या का उचित समाधान है। इस प्राधिकरण को यह भी पता है कि उपकरणों की कीमतें (जो पोर्ट प्रभार की गणना के लिए अहम हैं) बदल रही हैं तथा इस समय विनिर्दिष्ट प्रभारों की जल्दी ही समीक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने यह निश्चय किया है कि तीन प्रकार की पोर्ट-मांगों की श्रेणियों के लिए केवल तीन पोर्ट प्रभार ही विनिर्दिष्ट किए जाएं।
 - आठ पी सी एम (पीसीएम) तक (छोटे प्रयोक्ता)
 - आठ से अधिक तथा चौसठ पी सी एम तक (माध्यम प्रयोक्ता)
 - चौसठ पी सी एम से अधिक (बड़े प्रयोक्ता)
17. अंतः संयोजन चाहने वाले एक सुनियोजित अवधि के दौरान अपनी आवश्यक मांग का आकलन करके अपनी श्रेणी के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ यह प्रयास किया गया है कि तीनों श्रेणियों के प्रयोक्ताओं को उनकी विभिन्न स्तरीय पोर्ट की मांग के आधार पर समुचित रूप से व्यापक कवरेज मुहैया करवाया जाए। इससे समय-समय पर अलग-अलग मांग करने वालों के संचयीकरण की समस्या का समाधान हो जाएगा।
18. उपरोक्त इन तीनों श्रेणियों के लिए अनुसूची III में प्रति पोर्ट का औसत वार्षिक प्रभार विनिर्दिष्ट किया गया है। यह प्रभार, आठ पी सी एम की इकाई को आधार मानकर लागत के आधार पर 8 पी सी एम से 256 पी सी एम के लिए निकाला गया है। इन लागत आधारित प्रभारों के परिकलन की पद्धति वही है जिसका उल्लेख द्वितीय परामर्शी दस्तावेज में किया जा चुका है।
19. सेलुलर मोबाइल दूरसंचार सेवा के लिए 600 रुपये के विनिर्दिष्ट मासिक किराये में पी एस टी एन (पीएसटीएन) के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए किसी मोबाइल स्विचन केन्द्र में पोर्टों के प्रयोग की बात को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार सेलुलर मोबाइल का किराया कुल पूंजीगत लागत पर आधारित है जिसमें पोर्ट पर किया जाने वाला निवेश शामिल है। इसके अलावा 6 रुपये प्रति मिनट के एयर टाइम प्रभार में किसी मोबाइल स्विचन

केन्द्र के पोर्टो सहित कुल प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत शामिल है। इस प्रकार किसी मोबाइल स्विचन केन्द्र को पी एस टी एन के साथ संपर्क करने के लिए पोर्ट प्रभार देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर बताए गए अनुसार इस प्रकार का मूल्य निर्धारण के समय पहले ही जोड़ा जा चुका है।

20. तथापि, प्राधिकरण "अभिगम्यता/कैरिज प्रभार" के निर्धारण के संदर्भ में उपरोक्त पहलू पर और विचार करेगा। नई दूरसंचार नीति में इस बात की अनुमति दी गई है कि कोई भी सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क से किसी अन्य सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता सहित किसी भी अन्य प्रकार के सेवा प्रदाता के साथ अपने नेटवर्क को जोड़ सकता है। बुनियादी सुविधाओं की हिस्सेदारी की भी अनुमति दी गई है। अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रक्रिया सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा अतिरिक्त निवेश की स्थिति में उनको दिए जाने वाले पोर्ट प्रभारों को निर्धारण करने के एक स्पष्ट आधार उभर कर सामने आएगा।

(घ) राजस्व भागीदारी व्यवस्था

21. इस विनियम की अनुसूची 1 में उन कालों की राजस्व भागीदारी विनिर्दिष्ट की गई है जो एक बुनियादी सेवा प्रदाता के नेटवर्क से चलकर दूसरे बुनियादी सेवा प्रदाता के नेटवर्क से या तो होकर जाते हैं या उसके नेटवर्क पर समाप्त होते हैं।

22. अनुसूची 2 में उन कालों की राजस्व भागीदारी विनिर्दिष्ट की गई है, जो एक सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता के नेटवर्क से चलकर दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क से या तो होकर जाते हो यहाँ वहाँ समाप्त होते हो।

23. अनुसूची 1 के लिए दूसरे परामर्शी दस्तावेज में यह सुझाव दिया गया है कि एक नए सेवा प्रदाता तथा मौजूदा सेवा प्रदाता के बीच, में राजस्व भागीदारी इस प्रकार होनी चाहिए :

- घरेलू लंबी दूरी कालों के लिए संगत राजस्व का बंटवारा काल शुरू होने वाले सेवा प्रदाता तथा जिस प्रदाता के पास से काल होकर जाता है, के बीच 60 : 40 के अनुपात से होना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए यह अनुपात 45 : 55 का होगा;
- टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाता के साथ कोई राजस्व भागीदारी नहीं।

24. अन्वयों के साथ इस अनुपात का प्रस्ताव इस कारण से किया गया कि पी एस टी एन सेवा प्रदाताओं के लिए पूरी तरह से टैरिफ परिवर्तन करने से वर्तमान अथवा नए प्रवेशक के लिए मौजूदा राजस्व की स्थिति उन पर विपरीत प्रभाव न डाले। अतः प्रस्तावित अनुपात इस सिद्धान्त पर आधारित था कि किसी भी इंटरकनेक्टिंग सेवा प्रदाताओं पर अनुचित भार न पड़े। इस प्रकार, राजस्व हिस्सेदारी की मौजूदा प्रणाली को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि उक्त उल्लिखित अनुपात (जो 1.25 रु. प्रति मापित कॉल के कॉल प्रभार के काफी तदनु रूप है) टैरिफ दरों में लागू होगा जैसा कि विभिन्न कॉलों के लिए लागू है।

25. दूसरे परामर्श-पत्र में, बुनियादी दूरसंचार के लिए राजस्व की मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन करने की प्रकृति का सार इस प्रकार है :

"इस तथ्य को देखते हुए कि विभिन्न सेवाओं के लिए प्रस्तावित मूल्य, मूल्य-सीमा (प्राइस कैप) के रूप में हैं, इस के साथ-साथ बुनियादी सेवा प्रचालकों के लिए राजस्व भागीदारी पर सुझाव दिए गए हैं। इससे राजस्व भागीदारी की मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए, बुनियादी सेवा क्षेत्र में जहाँ लंबी दूरी और अंतर-राष्ट्रीय कॉल राजस्व के लिए क्रमशः 60 : 40 और 45 : 55 की प्रति पल्स (रु. 0.50 लंबी दूरी तथा रु. 0.70 अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए) राजस्व भागीदारी की विशिष्ट राशि के भुगतान की वर्तमान शर्त नए प्रचालक और DOT यानि दूर संचार विभाग के लिए प्रस्तावित है (नए प्रचालक के नेटवर्क से शुरू होने वाली और DOT द्वारा पहुँचाई जाने वाली किसी कॉल के लिए)" (अध्याय 1 पृष्ठ 13)।

26. प्रस्तावित व्यवस्था लागू करने में तकनीकी दिक्कतों तथा यह अहता जहाँ प्रत्येक नए सेवा प्रदाता के लिए कॉल शुरू और समाप्त करने की कॉलों की संख्या समान होने की संभावना होती है, के कारण दूसरे परामर्श पत्र में टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाता के लिए किसी राजस्व भागीदारी का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

27. अपनी टिप्पणियों में दूरसंचार विभाग ने प्रस्तावित राजस्व भागीदारी की सहमति दी है बशर्ते कि वे रु. 1.30 प्रति कॉल की दर लागू करें। यह उल्लेखनीय है कि दूसरे परामर्श पत्र में 1.30 रुपए प्रति मोटरित कॉल की कॉल प्रभार का प्रस्ताव किया था जिसे दूरसंचार टैरिफ आर्डर 1999 द्वारा 1.20 रुपए प्रति मोटरित कॉल की अधिकतम सीमा तक कम किया गया। दूरसंचार विभाग की टिप्पणियों से उद्धृत :

"प्राइवेट और दूरसंचार विभाग के बीच STD और ISD राजस्व के लिए क्रमशः 60 : 40 और 45 : 55 का टी आर ए आई के प्रस्तावित राजस्व हिस्से को, अधिकतम कॉल टैरिफ अर्थात् PSTN कॉल के लिए 1.30 रुपए तथा ISDN कॉल के लिए 1.50 रुपए पर लागू किए जाने की आवश्यकता है।"

28. दूरसंचार विभाग की टिप्पणियों के विपरीत, बुनियादी सेवा प्रदाताओं के संघ (ABTO) ने यह टिप्पणी की कि नए प्रचालक को संबद्ध राजस्व का 75 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए और 25 प्रतिशत हिस्सा दूरसंचार को दिया जाना चाहिए। यह दावा इस तर्क पर आधारित था कि स्थानीय कॉल क्षेत्र में सौंपी गई कालों सहित नए प्रचालक को सुपुर्द की गई सभी STD और ISD कॉलों के लिए दूरसंचार विभाग को अदायगी करनी चाहिए। ISD कॉलों के लिए राजस्व भागीदारी में DOT द्वारा लेखा संबंधी दर तंत्र के ढाँचे के भीतर विदेशी संवाहकों को/से अदा/प्राप्त किया गया राजस्व शामिल है। इस आधार पर ABTO ने सुझाव दिया है कि संबंधित ISD राजस्व का बंटवारा 75 : 25 के अनुपात में नए प्रचालक और दूरसंचार विभाग के बीच किया जाए।

29. प्रारम्भ में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि इस विनियम में विनिर्दिष्ट राजस्व भागीदारी की व्यवस्थाएं अस्थायी हैं और वे विस्तृत लागत विश्लेषण पर आधारित नहीं हैं। संपर्क/कैरिज प्रभार की प्रथा को लागू करने से तर्कसंगत उपयोग प्रभार प्रदान नहीं करेगा। इसके लिए निर्धारित लागत का विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मौजूदा राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन करने होंगे, अतः सेवा प्रदाताओं के

लिए राजस्व व्यवस्थाओं का भी विश्लेषण करना अपेक्षित है। राजस्व भागीदारी सिद्धांत के बारे में ABTO द्वारा भी ऐसे ही सुझाव दिए गए हैं जब तक कोई संपर्क/कैरिज प्रभार की व्यवस्था लागू नहीं की जाती तब तक अंतःसंयोजन के जरिए उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक संबंधों को जारी रखने के लिए राजस्व भागीदारी की व्यवस्था यथावत रखी जाए।

30. जैसा कि ऊपर बताया है कि बुनियादी सेवाओं के लिए राजस्व भागीदारी का निर्धारण करने की विशेष चिंता यह थी कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं (वर्तमान अथवा नए प्रचालक) को किसी भी तरह के टैरिफ परिवर्तन, जिसने राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था बदल जाती हो, के परिणामों को बराबर वहन करना चाहिए अतः दूरसंचार टैरिफ आर्डर 1999 में अंतिम रूप से टैरिफ विनिर्दिष्ट होने पर भी यह टैरिफ परामर्शी दस्तावेज में (अर्थात् पहले 1.30 रुपये के स्थान पर 1.20 रुपये प्रति मीटरित कॉल) में उन प्रस्तावित टैरिफ से भिन्न थे जिनमें यह व्यवस्था की गई थी कि यथा प्रस्तावित वही भागीदारी, परामर्शी दस्तावेज में पहले प्रतिबिम्बित संतुलन प्रदान करेगी। अनुसूची 1 में निर्दिष्ट रु. 0.48 प्रति मीटरित (लंबी दूरी) कॉल की राशि रु. 1.20 तथा रु. 0.66 प्रति मीटरित (अंतर्राष्ट्रीय) कॉल का 40 प्रतिशत, और 1.20 रुपये का 55 प्रतिशत होगी। इससे पता चलता है कि जैसा प्रस्ताव पहले किया गया है कि सेवा प्रदाता राजस्व भागीदारी में एक अनुपात में रु. 1.30 से रु. 1.20 तक कॉल प्रभार में हुई कटौती को सहन करेंगे। यहां इस बात पर पुनः जोर दिया जाना चाहिए कि ऐसे अनुपातों को, राजस्व हिस्सेदारी निर्धारित करने के एक अस्थायी उपाय के रूप में लागू किया जाता है जिन्हें संपर्क/कैरिज व्यवस्था में लागू नहीं किया जाएगा।

31. संक्षिप्त में, प्राधिकरण ने अनुसूची 1 में यह निर्दिष्ट किया है कि :

- कॉलों की संख्या को मापने की वह प्रणाली जिसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, वर्तमान की भांति यथावत् रहेगी,
- घरेलू लंबी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कॉलों के लिए राजस्व हिस्सेदारी की गणना रु. 1.20 अर्थात् दूर संचार टैरिफ आर्डर 1999 में निर्दिष्ट अधिकतम कॉल प्रभार पर आंकी गई प्रति मीटरित कॉल की राशि के रूप में की जाएगी,
- इससे पता चलता है घरेलू लंबी दूरी की कॉलों के लिए रु. 0.48 प्रति मापित कॉल पर तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए रु. 0.66 प्रति मापित कॉल पर भुगतान किया जाना चाहिए।
- दूर संचार विभाग और VSNL के बीच राजस्व भागीदारी व्यवस्था संबंधी कोई उल्लेख अनुसूची में नहीं किया गया है।

32. अनुसूची II में सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली कॉलों के लिए राजस्व भागीदारी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इन कॉलों के लिए भी राजस्व भागीदारी व्यवस्थाएं वही रहेंगी जैसी कि पूर्व में मौजूद हैं। खास बदलाव यह है कि पहले प्रयुक्त रु. 1.40 प्रति मापित कॉल के कॉल प्रभार के स्थान पर अब रु. 1.20 प्रति मापित कॉल प्रभार लिया जाएगा।

33. दूसरे परामर्शी दस्तावेज में यह सवाल उठाया गया था कि बुनियादी सेवा प्रदाताओं की भांति, सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को लम्बी दूरी की कॉल राजस्व का हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता ऐसे राजस्व भागीदारी के पक्ष में थे लेकिन बुनियादी सेवा प्रदाताओं ने इसका विरोध किया। प्राधिकरण ने ऐसी राजस्व भागीदारी प्रदान न करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यद्यपि बुनियादी सेवा प्रदाताओं के पास लम्बी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय कॉल प्रभारों से अतिरिक्त धन मिल जाता है जबकि सेल्यूलर मोबाइल सेक्टर की स्थिति कुछ भिन्न है। सेल्यूलर मोबाइल सेक्टर के लिए विनिर्दिष्ट टैरिफों में ऐसी लाभकारिता दी गई है जो "मोडियन" लागत प्राक्कलन (न कि सक्षम सेवा प्रदाता की लागत पर आधारित निम्न प्राक्कलन पर) आधारित है। किराये में पूंजी लागत और लाइसेंस शुल्क की आधा धनराशि (मेट्रो क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं के लिए) शामिल है। 6 रु. प्रति मिनट के एयर टाइम प्रभार के परिकलन में लाइसेंस शुल्क का दूसरा आधा भाग, प्रचालन लागत और लाभ को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा अनुपूरक सेवाओं के लिए प्रभार फारवियरेंस या निरपेक्षता निर्दिष्ट किया गया है जो पर्याप्त राजस्व के लिए एक आधार प्रदान करेगा तथा सेल्यूलर मोबाइल टैरिफ के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सर्किल से सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता के दूसरे उपभोक्ताओं को की गई लंबी दूरी की कॉलों के लिए टैरिफ में लचीलापन प्रदान किया गया है। अतः इस समय सेल्यूलर मोबाइल से की गई लम्बी दूरी की कॉलों के लिए सेल्यूलर मोबाइल और बुनियादी सेवा प्रदाताओं के बीच राजस्व भागीदारी का कोई आधार नजर नहीं आता है।

34. सेल्यूलर मोबाइल से संबंधित राजस्व भागीदारी व्यवस्था कालिंग पार्टी अदा टैरिफ व्यवस्था के लागू होने के साथ बदलती रहेंगी। संपर्क/कैरिज प्रभार व्यवस्था के लागू होने से ऐसी व्यवस्था में भी बदलाव होगा।

(इ.) कुछ अन्य विशेषताएं

35. इस नियम में, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की भांति, रिपोर्टिंग की शर्त तथा अंतः संयोजन प्रभार अथवा राजस्व भागीदारी व्यवस्था, चाहे उसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो अथवा अंतः संयोजन प्राप्तकर्ता और प्रदाता के बीच पारस्परिक सहमति की समीक्षा करने तथा उनमें हेरफेर करने, संबंधी प्राधिकरण की संभावना को शामिल किया गया है।

36. इसी तरह दूरसंचार टैरिफ, आदेश 1999 की तरह, विनियम में कहा गया है कि इसके द्वारा निहित मामलों में, विनियम के प्रावधानों को प्रारंभिक टॉजिट अथवा टर्मिनेटिंग सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्दिष्ट लाइसेंस अथवा अंतः संयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं की तुलना में अति प्राथमिकता दी जाएगी।

37. जैसा कि ऊपर बताया गया है। इस विनियम में अंतः संयोजन के संबंध में अंतः संयोजन प्रभार और राजस्व भागीदारी व्यवस्थाओं का उल्लेख है। अंतः संयोजन से संबंधित अन्य नियमों एवं विनियमों को प्राधिकरण द्वारा या तो अन्यत्र निर्दिष्ट किया गया है अथवा प्राधिकरण के नियम/आदेशों द्वारा इनका उल्लेख किया जाएगा। इसमें अंतः संयोजन, अंतः संयोजन प्रदान करने की तकनीकी व्यवहारिता तथा अंतः संयोजन सेवाओं की क्वालिटी की मुद्दों पर सहमति जैसे पहलू शामिल किए गए हैं।

हर्ष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/142/99]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

New Delhi, the 28th May, 1999

No. 311-I/99-TRAI (Econ.).—In exercise of the powers conferred upon it under section 36 read with clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to ensure effective interconnection between different service providers and to regulate arrangements amongst service providers of sharing their revenue derived from providing telecommunication services, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Regulation.

**THE TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION (CHARGES AND
REVENUE SHARING) REGULATION 1999
(1 of 1999)**

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement:
 - (i) This Regulation shall be called “The Telecommunication Interconnection (Charges and Revenue Sharing) Regulation 1999.”
 - (ii) The Regulation shall cover arrangements among service providers for interconnection charges and revenue sharing, for all Telecommunication Services throughout the territory of India, as also those originating in India and terminating outside India.
 - (iii) The Regulation shall be deemed to have come into force with effect from May 1, 1999.

Section II

Definitions

2. In this Regulation, unless the context otherwise requires:
 - (i) “Act” means the Telecom Regulatory Authority Act of India, 1997.
 - (ii) “Authority” means the Telecom Regulatory Authority of India.

- (iii) "Basic Telecommunication Services" mean services derived from Public Switched Telephone Network (PSTN).
- (iv) "Ceiling(s)" mean(s) the upper limit(s) for interconnection charge for telecommunication services as may be specified by the Authority from time to time.
- (v) "Domestic Long Distance Telecommunication Service" or DLD means the telecommunication services required to connect one local area of a public telecommunication network to another within the territorial limits of India so as to allow for transmission of voice and non-voice signals across different geographical areas.
- (vi) "Floor" means the lower limit of interconnection charges for a telecommunication service as may be specified by the Authority from time to time below which such charges may not be offered.
- (vii) "Forbearance" denotes that the Authority has not, for the time being, notified any interconnection charge or revenue sharing arrangement for a particular telecommunication service and the service provider is free to fix any charge for such service.
- (viii) "Interconnection" means the commercial and technical arrangements under which service providers connect their equipment, networks and services to enable their customers to have access to the customers, services and networks of other services providers.
- (ix) "Interconnection Charge" means the charge for interconnection by an interconnection provider to an interconnection seeker.
- (x) "Interconnection Provider" means the service provider to whose network an interconnection is sought for providing telecommunication services.
- (xi) "Interconnection Seeker" means the service provider who seeks interconnection to the network of the interconnection provider.
- (xii) "International Long Distance Telecommunication Service" means telecommunication services required to connect a local area of a public telecommunication network within India to a local area of a public telecommunication network in another country so as to allow for the transmission of voice and non-voice signals.
- (xiii) "International Subscriber Dialing" or ISD means direct interconnection between an end user in India with another end user in another country by means of direct dialing through public networks.

- (xiv) "Leased Circuits" mean telecommunication facilities leased to subscribers or service providers to provide for technology transparent transmission capacity between network termination points which the user can control as part of the leased circuit provision and which may also include systems allowing flexible use of leased circuit bandwidth.
- (xv) "Non-discrimination in interconnection charge" means that service providers shall not, in the matter of interconnection charges, discriminate between service providers except on the basis of substantial cost-differential, and that too only to the extent justified by such cost differential.
- (xvi) "Order" means the Telecommunication Tariff Order 1999.
- (xvii) "Originating Network" means the network to which an originator of a telecommunication message is proximately connected to.
- (xviii) "Originating/Transit/Terminating Service Provider" means the service provider whose network is used for originating/transit/terminating a telecommunication message.
- (xix) "Port Charges" mean charges payable by the interconnection seeker to the interconnection provider for terminating the interconnection links on the network interface of the interconnection provider.
- (xx) "Regulation" means The Telecommunication Interconnection (Charges and Revenue Sharing) Regulation 1999.
- (xxi) "Reporting Requirement" means the obligation of a service provider to report to the Authority at least 45 working days before implementing any new interconnection charge and revenue sharing arrangement for telecommunication services under this Regulation and any changes thereafter.
- (xxii) "Set Up Costs Of Interconnection" means the initial cost of any engineering work needed to provide the specific interconnection facilities requested.
- (xxiii) "Subscriber Trunk Dialing" or STD means direct interconnection between two end users within India by means of direct dialing through public networks.
- (xxiv) "Terminating Network" means the network to which a receiver of a telecommunication message is proximately connected to.
- (xxv) "Transit Network" means the network through which telecommunication messages from originating networks or other transit networks are transited and delivered to terminating or other transit networks

- (xxvi) "Usage Charge" means the charge by a service provider for carriage/delivery/collection of telecommunication messages in its network.
- (xxvii) Words and expressions used in this Regulation and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

Section III

3. Interconnection Charges

- (i) Interconnection charges shall be cost based, unless as may be specified otherwise.
- (ii) For determining cost based interconnection charges, the main basis shall be "incremental or additional" costs directly attributable to the provision of interconnection by the interconnection provider.
- (iii) No service provider shall discriminate between service providers in the matter of levying of charges for interconnection.

Provided that a different charge may be levied if justified on the basis of a substantial difference in costs incurred for providing that particular interconnection.

- (iv) No service provider shall be charged for any interconnection facility it does not seek or require.

Provided that if interconnection facility cannot be provided in the form that is sought or required by the interconnection seeker, the issue may be decided mutually between the seeker and provider of interconnection. In case such mutual agreement is not possible, the matter may be reported to the Authority for a decision. The interconnection provider shall inform the interconnection seeker within 45 days of the request for interconnection facilities whether the facilities can be provided in the form sought or required by the interconnection seeker.

- (v) Charges for certain elements of the network used to provide interconnection are specified in the Schedules to this Regulation. Interconnection charges in respect of leased circuits and internet port charges shall be the same as the tariffs for these services specified, respectively, in Schedules IV and VI of the Telecommunication Tariff Order 1999.
- (vi) Unless specifically so provided, the Authority has forbore with respect to interconnection charges.

- (vii) Where the Authority has, for the time being, forborne from specifying interconnection charges, interconnection seekers and providers shall mutually decide on such charges.
- (viii) Interconnection charges mutually agreed among interconnection seeker and provider shall be based on the principles enunciated in this Section.
- (ix) Where mutual agreement for interconnection charge cannot be reached within three months of initiating such a process for charges with respect to which the Authority has forborne, the Authority may intervene to settle the matter *suo moto* or on the application of either party.

Section IV

4. Revenue Sharing Arrangements

- (i) Any revenue sharing among interconnection seeker and interconnection provider shall take place out of the proceeds of the amount payable by the subscriber for obtaining the service which involves the usage of the network of the interconnection provider.
- (ii) Unless specifically provided in the Schedules to this Regulation, the Authority forebears with respect to revenue sharing arrangements.
- (iii) Where the Authority has, for the time being, forborne from specifying revenue sharing arrangements for any telecommunication service or part thereof, service providers shall mutually decide on such arrangements.
- (iv) Where mutual agreement for revenue sharing cannot be reached within three months of initiating such a process for revenue sharing with respect to which the Authority has forborne, the Authority may intervene to settle the matter *suo moto* or on the application of either party.

Section V

5. Reporting Requirement

- (i) All service providers shall comply with the Reporting Requirement in respect of interconnection charges and revenue sharing arrangements specified for the first time under this Regulation, as also all subsequent changes. This includes interconnection charges and revenue sharing arrangements that are decided on a mutual basis among service providers.
- (ii) The service provider may implement the proposed interconnection charges and revenue sharing arrangements after the mandatory notice period of 45 working days, unless the Authority within such period directs otherwise.

Except that an additional period of 45 days is provided for interconnection charges and revenue sharing arrangements to be reported to the Authority for the first time after the implementation of this Regulation.

- (iii) When an interconnection provider informs the interconnection seeker that it cannot provide interconnection as sought for by the latter, the interconnection seeker, within 45 days of being so informed, may approach the Authority for seeking its intervention.
- (iv) No service provider shall alter any interconnection charge or revenue sharing arrangement, or any part thereof, without complying with the Reporting Requirement.

Section VI

6. Review

- (i) The Authority may, from time to time, review and modify an interconnection charge and/or revenue sharing arrangements.
- (ii) The Authority may also at any time, on reference from any affected party, and for good and sufficient reasons, review and modify any interconnection charge or revenue sharing arrangements.

Section VII

7. Explanatory Memorandum

This Regulation contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to matters covered under this Regulation.

Section VIII

Residuary Clauses

8. Over-riding Effect

Provisions of this Regulation in respect of interconnection charges and revenue sharing shall have over-riding effect over the terms and conditions of the license of a service provider, as also any conditions or charges prescribed by an originating/transit/terminating service provider.

9. Interpretation

In case of dispute regarding interpretation of any of the provisions of this Regulation, the decision of the Authority shall be final and binding.

SCHEDULE I
INTERCONNECTION CHARGE AND REVENUE SHARING

<u>ITEM</u>	REVENUE SHARING FOR BASIC SERVICES
<u>(1) Date of Implementation</u>	01 May, 1999
<u>(2) Coverage</u>	Calls originating in a basic service provider's network and transmitted through or terminated in another basic service provider's network.
<u>(3) Local calls</u>	Bill and keep for each service provider.
<u>(4) Domestic long distance calls (STD calls)</u>	<p>The originating/transit service provider to pay Rs. 0.48 per unit of measured call for traffic delivered from its network to the network of the transit/terminating service provider for the call units measured at the point of interconnection for its further carriage from the point of interconnection to destination, based on the STD pulse rate.</p> <p>Provided no such charge shall be payable if the point of interconnection is at the destination Short Distance Charging Area (SDCA) and also provided that no such charge will be payable if the terminating service provider requests that the call be handed over by the originating/transit service provider at an SDCA other than the destination SDCA.</p>
<u>(5) International calls</u>	The originating service provider to pay Rs. 0.66 per unit measured call to the transit service provider (at present the Department of Telecommunications), for the call units to be measured at the point of interconnection.
	<p><u>Notes:</u></p> <p>(a) "Local calls" are calls which originate from subscribers of a service provider's network/exchange system in a SDCA and terminate either (i) within the same SDCA or (ii) in the contiguous telephone exchange system of the adjacent SDCA, provided these are delivered/handed over to another service provider's network in the destination SDCA only.</p> <p>(b) For domestic long distance calls, number of units of calls for payment at Rs. 0.48 per metered call to be calculated based on the STD tariff pulse for the radial distance between the point of interconnection and the Gateway Tax where the call is subsequently delivered for further carriage/termination.</p> <p>(c) No revenue is to be shared between basic service provider and cellular mobile service provider for calls originating from the former's network.</p> <p>(d) This Schedule does not address revenue sharing arrangement between Videsh Sanchar Nigam Limited and the Department of Telecommunication, nor between the Indian and foreign carriers of international calls.</p>

SCHEDULE II
INTERCONNECTION CHARGE AND REVENUE SHARING

<u>ITEM</u>	REVENUE SHARING FOR CELLULAR MOBILE
<u>(1) Date of Implementation</u>	01 May, 1999
<u>(2) Coverage</u>	Calls originating in a cellular mobile service provider's network and transmitted through or terminated in another service provider's network.
<u>(3) Local calls from cellular mobile to basic service subscriber</u>	Payment to basic service provider at the rate of Rs. 1.20 per metered call, with number of metered calls measured at the pulse rate applicable to a basic service local call.
<u>(4) Domestic Long distance calls from cellular mobile to basic service subscriber</u>	Payment to basic service provider at a rate applicable to domestic long distance calls. The charge shall be Rs. 1.20 per metered call, with the number of metered calls measured at the pulse rate applicable to basic service long distance calls, with the chargeable distance equal to the distance of the call carried by the basic service provider for an equivalent STD from point of interconnection to destination.
<u>(5) International calls from cellular mobile</u>	Payment to basic service provider at a rate applicable to international calls. The charge shall be Rs. 1.20 per metered call, with the number of metered calls measured at the point of interconnection at a pulse rate applicable to an equivalent international call made by a basic service subscriber.
<u>(6) For calls from cellular mobile to cellular mobile</u>	For local/domestic long distance calls carried (partly) by basic service provider, an amount to be paid to basic service provider at a rate applicable to local/domestic long distance call. The amount to be calculated on the basis of the corresponding conditions specified in Item 3/Item 4 above, i.e. Rs. 1.20 per metered call, pulse rate applicable to basic service local/long distance calls, and for long distance calls the chargeable distance equal to the distance of the call carried by the basic service provider for an equivalent STD call from point of interconnection to destination.
	<p><u>Notes:</u></p> <p>(a) The definition of "local calls" to ascertain revenue sharing with basic service providers for calls carried by them is the same as in note (a) in Schedule I.</p> <p>(b) For domestic long distance calls from cellular mobile to basic service subscriber, number of units of measured calls for determining the amount of revenue payable to basic service provider to be calculated as the number of such calls measured at the basic service provider's Gateway TAX up to the destination Short Distance Charging Area (SDCA).</p> <p>(c) For domestic long distance calls from cellular mobile to cellular mobile carried by basic service provider, number of call units to be paid to the basic service provider at Rs. 1.20 per metered call to be calculated based on the radial distance between the Gateway TAX at the point of interconnection where the call is accepted for further carriage and the Gateway TAX of the service provider to whose network the call is</p>

	<p>subsequently handed over.</p> <p>(d) For calls originating from cellular mobile, revenue sharing arrangements among one basic service provider and another basic service provider to be as specified in Schedule I.</p> <p>(e) This Regulation does not specifically address any revenue sharing arrangement among cellular mobile service providers for calls from subscribers of any cellular mobile service provider to subscribers of another cellular mobile service provider.</p>
--	--

SCHEDULE III
INTERCONNECTION CHARGE AND REVENUE SHARING

<u>ITEM</u>	<u>PORT CHARGES</u>								
<u>(1) Date of Implementation</u>	01 May, 1999								
<u>(2) Coverage</u>	Charges for ports provided by service providers (other than the port charges for internet, which are specified in Schedule VI of the Telecommunication Tariff Act 1998.)								
<u>(3) Port Charges</u>	<table> <tr> <th><u>Number of PCMs</u></th><th><u>Annual Charge</u> <u>(Ceiling of Rs. per port)</u></th></tr> <tr> <td>Up to 8</td><td>37,000</td></tr> <tr> <td>Above 8 and up to 32</td><td>16,000</td></tr> <tr> <td>Above 32</td><td>9,000</td></tr> </table>	<u>Number of PCMs</u>	<u>Annual Charge</u> <u>(Ceiling of Rs. per port)</u>	Up to 8	37,000	Above 8 and up to 32	16,000	Above 32	9,000
<u>Number of PCMs</u>	<u>Annual Charge</u> <u>(Ceiling of Rs. per port)</u>								
Up to 8	37,000								
Above 8 and up to 32	16,000								
Above 32	9,000								

ANNEX A**EXPLANATORY MEMORANDUM****A. INTRODUCTION**

1. This Regulation is a result of a consultation process which began in November 1997 with the release of a consultation paper that addressed concepts, principles and methodologies relating to telecom tariffs and commercial aspects of interconnection. After extensive discussions, some specific proposals for interconnection charges and revenue sharing arrangements were made in another consultation paper released on 9 September, 1998. These too were subject to extensive and intensive discussions with various service providers and other interested parties, including several national and international experts in the area.
2. A comprehensive framework of regulations for interconnection involves both commercial and other aspects. This Regulation deals only with interconnection charges and revenue sharing arrangements. Other, complementary, regulations and directives will be addressed elsewhere by the Authority.
3. The purpose of this Memorandum is to lend clarity and transparency to the main rules and schedules of this Regulation, as also to explain that for some interconnection charges, tariffs specified by the Authority in its Telecommunication Tariff Order 1999 are the relevant charges.
4. The determination of interconnection charges and revenue sharing should take into account both the prevailing situation in the telecommunication sector in India, as well as the prospective liberalization in that sector, as is reflected in the National Telecom Policy 1999. These policy changes, as well as technological developments and their effects of costs, and application of new tariff system for certain services (e.g. introduction of calling party pays principle in the cellular mobile segment of the market) could alter the cost basis for the interconnection charge and revenue sharing arrangements that have been specified in this Regulation.
5. Thus, this Regulation contains certain elements which will change with time, following an analysis of more detailed data on network components. Such a process had also been indicated in the Authority's second consultation paper (Consultation Paper No. 98/3, dated September 9, 1998), which stated that:

“Technological and commercial developments in various segments of the telecom markets, e.g. leased lines, affect the basis for determining interconnection charges. In addition to these changes, more detailed and up-to-date information on costs will be available over time, which will provide a better insight into the basis for determining interconnection charges. A review of interconnection charges would therefore be required in due time. Hence the proposals on

interconnection prices, other than those relating to general principles, should be viewed as interim measures to be reviewed and adjusted, if required.” (see Chapter VIII, page 44 of the second consultation paper)

6. The Authority is preparing a consultation paper on access/carriage charge regime. Access/carriage charges will provide for an efficient interconnection regime in a situation with multiple service providers interconnecting with each other, i.e. the telecom environment envisaged in the National Telecom Policy 1999.
7. Work is also underway in the Authority for preparing a consultation paper on accounting separation for telecommunication service providers. Implementation of accounting separation is very important for determining cost based interconnection charges and revenue sharing arrangements, but this is a time consuming process. The Authority's consultation paper on access/carriage charges will take into account certain aspects of accounting separation in order to determine an access/carriage charge regime in the near future. Any further refinements will be made, if required, when the accounting separation exercise provides more detailed information.

B. SCOPE OF CERTAIN TERMS USED IN THE REGULATION

8. The payment by any service provider for connection and use of the network of another service provider is conceptually divided as under:
 - **set-up costs**, i.e. all costs required for initially linking up two networks and making that link operational (including inputs such as fibre links, ports, building space and any up-gradation of equipment, as well as software required to make the interconnection operational).
 - **interconnection charges** are the (recurring) amounts payable for the set-up costs;
 - **usage charges** are payments for use of the network for transmission of telecommunications messages by the subscriber of the interconnection seeker. The mode of payment of such charges includes, *inter alia*, revenue sharing arrangements

C. INTERCONNECTION CHARGES

(a) Basis

9. Among the main points that emerged during the consultation process was that interconnection pricing should be
 - based mainly on incremental or additional costs directly attributable to provision of interconnection, and
 - applied on a non-discriminatory basis.

10. The Regulation has specified these principles as the main basis for determining interconnection charges. These principles will also figure prominently in the work of the Authority on determination of access/carriage charges.
- (b). **Interconnection Charges specified by the Authority**
11. The Authority has specified three types of interconnection charges, i.e.:
 - leased circuits (same as in Schedule IV of the Telecommunication Tariff Order 1999);
 - port charges for internet (same as in Schedule VI of the Telecommunication Tariff Order 1999);
 - port charges for connection to exchanges of service providers (Schedule III of this Regulation), other than above-mentioned port charges for internet.
12. These charges are based mainly on costs. As mentioned in the second consultation paper as well as this Regulation, they will be subject to periodic review and changes, as appropriate.
13. Interconnection charges for leased circuits are the same as the corresponding tariffs for leased circuits specified in Schedule IV of the Telecommunication Tariff Order 1999. The same (i.e. tariffs applied as interconnection charges) is also valid for internet port charges. Tariffs for internet leased circuits (port charges) are specified in Schedule VI of the Telecommunication Tariff Order 1999.
14. Schedule VI of the Telecommunication Tariff Order 1999 does not specifically address tariffs for international leased lines, because these tariffs are subject to forbearance in that Schedule. This is also applicable to interconnection charges for international leased circuits. The Authority plans to conduct a detailed analysis for specifying the values for international leased line charges both as tariffs and interconnection charges.
15. Schedule III of this Regulation specifies port charges to be charged by service providers. A comment during consultation was that for determining port charges, there should be a possibility of cumulating the demands for ports made at different points of time by any interconnection seeker. Such cumulation would imply a lower charge per port than the charges applied individually to the different demands for ports. In contrast, those supplying ports were of the view that each separate demand for ports involved additional expenditure and should therefore be charged separately, without aggregating it with the previous/later demand for ports by any interconnection seeker.
16. The Authority has considered these points in detail, including the additionality of investment for providing ports. It has concluded that a simplified charging solution is an appropriate means of addressing this problem. The Authority further recognizes that equipment prices (that underlie the calculation of port charges) are changing, and there will soon be a need to review the amounts

presently specified for port charges. Bearing these in mind, the Authority has decided to specify only three port charges by linking them to three categories of demand for ports:

- up to eight PCMs (small users);
- above eight and up to sixty-four PCMs (medium users);
- above sixty-four PCMs (large users).

17. Interconnection seekers can assess their potential demand over a planning period, and decide which of the three categories would apply to them. The attempt here has been to provide a reasonably wide coverage within each of the three different usage categories corresponding to different levels of demand for ports. This will help overcome the problems that arise in tackling the issue of cumulating demands made at different periods.
18. For each of these three categories mentioned above, Schedule III specifies a corresponding average annual charge per port. These charges are derived on the basis of cost based charges for units of eight PCMs, starting from eight PCMs and going up to 256 PCMs. The method for calculating these cost based charges is the same as mentioned in the second consultation paper.
19. The monthly rental of Rs. 600 specified for cellular mobile telecommunication services takes into account the use of ports in a mobile switching centre to provide connectivity with PSTN. The rental for cellular mobile is thus based on total capital cost incurred in providing the service, which includes the investment on ports. Further the air time charge of Rs. 6 per minute provides for the total operating and maintenance costs incurred on the asset, including the ports of a mobile switching centre. Thus charges for the port of a mobile switching centre used for providing connectivity to the PSTN need not be paid for, having already been taken into account in costing as explained earlier.
20. The above aspect will, however, be further addressed by the Authority in the context of determination of "access/carriage charges". The new National Telecom Policy permits interconnectivity of network of a cellular mobile service provider with that of any other type of service provider, including the network of another cellular mobile service provider. Sharing of infrastructure is also permitted. The exercise will, inter alia, provide a clear basis for determination of port charges payable to cellular mobile service providers as they make additional investment.

D. REVENUE SHARING ARRANGEMENTS

21. Schedule I of this Regulation specifies revenue sharing arrangements for calls originating from basic service provider's network and carried by or terminated in the network of another basic service provider.

22. Schedule II specifies revenue sharing arrangements for calls originating from the network of a cellular mobile service provider and carried by or terminated in another service provider's network.
23. For Schedule I, the second consultation paper had proposed that revenue be shared as follows between new service provider and the incumbent:
- for domestic long distance calls, relevant revenue to be shared in the ratio 60:40 between the originating service provider and the transit service provider;
 - for international calls, this ratio to be 45:55;
 - no revenue sharing with the terminating service provider.
24. These ratios had been proposed, among others, for reasons that with the overall tariff changes for PSTN service providers, the prevailing revenue situation for either the incumbent or the new entrant should not be adversely affected in a major way. The ratios proposed were hence based on the principle that there should not be an undue burden on any of the interconnecting service providers. Thus, in the prevailing system of revenue sharing, it was proposed that the above-mentioned ratios (which broadly corresponded to a call charge of Rs. 1.25 per measured call) apply to the tariff rates as applicable to different calls.
25. In the second consultation paper, the nature of the change in the prevailing system of revenue sharing for basic telecom was summarized as follows:
- "In view of the fact that proposed prices for various services are in the form of price caps, revenue shares are suggested, inter alia, for basic telecom operators. This alters the present system of revenue sharing. For example, in the basic services sector where the current condition requires a payment of specific amounts per pulse (Rs. 0.50 for long distance, and Rs. 0.70 for international), revenue shares of 60:40 and 45:55, respectively, for long distance and international call revenue are proposed for new entrant and DOT [for a call originating from the network of the new entrant and carried by DOT]." (Chapter I, page xiii)*
26. The second consultation paper had proposed no revenue sharing for the terminating service provider because of the technical difficulty in implementing the proposed arrangement, and the premise that there would likely be similar number of calls originating and terminating for each new service provider.
27. In its comments, the DOT agreed to the proposed revenue shares, provided that they applied to the rate of Rs. 1.30 per PSTN call. It should be recalled that the second consultation paper had proposed a call charge of Rs. 1.30 per metered call, which was reduced by the Telecommunication Tariff Order 1999 to an upper limit of Rs. 1.20 per metered call. To quote from the DOT's comments:

“TRAI’s proposed revenue shares of 60:40 and 45:55 respectively for STD and ISD revenue between private operators and DOT need to be made applicable on the highest call tariff, i.e. Rs. 1.30 for PSTN call and Rs. 1.50 for ISDN call”

28. In contrast to the DOT, the Association of Basic Service Operators (ABTO) commented that the new entrants should get 75 per cent of the relevant revenue, with 25 per cent to be given to the DOT. This claim was based on the argument that DOT should pay for all STD and ISD calls handed over to the new entrant, including those which are handed over in the local call area. For ISD calls, the revenue share includes the revenue paid/received by DOT to/from foreign carriers within the framework of the accounting rate mechanism. On this basis, the ABTO suggested that the relevant ISD revenue should be shared among new entrant and DOT in the ratio of 75:25.
29. To begin with, it must be re-iterated that the revenue sharing arrangements specified in this Regulation are interim, and are not based on detailed cost analysis. Application of an access/carriage charge regime will provide more logically tenable usage charges. That requires a detailed assessment of the underlying costs. It would, moreover, imply major changes to the existing revenue sharing arrangements, and hence an analysis is required also of the revenue implications for service providers. This is so also for suggestions made by ABTO regarding revenue sharing principles. Till any access/carriage charge regime is implemented, a system of revenue sharing must be in place to give effect to the commercial relationships arising through interconnection.
30. As mentioned above, an important concern for determining the revenue shares for basic services was that different service providers (incumbent or the new entrant) should bear in a balanced manner the consequences of any tariff change that alters the revenue sharing arrangement. Hence, even though the tariffs finally specified in the Telecommunication Tariff Order 1999 are different from those proposed in the consultation paper (e.g., Rs. 1.20 per metered call instead of Rs. 1.30 earlier), maintaining the same shares as proposed would provide the balance reflected earlier in the consultation paper. The amount of Rs. 0.48 per metered (long distance) call that is specified in Schedule I corresponds to 40 per cent of Rs. 1.20, and Rs. 0.66 per metered (international) call corresponds to 55 per cent of Rs. 1.20. This implies that the service providers sharing revenue bear the reduction in call charge from Rs. 1.30 to Rs. 1.20 in the same proportion as was proposed earlier. It must again be emphasized here that these proportions are applied as an interim measure for determining revenue shares, and will not apply in the access/carriage charge regime.
31. In summary, the Authority has specified in Schedule I that:
 - the system of measuring the number of calls for which payment has to be made continue to be the same as at present;

- for both domestic long distance and international calls, the revenue share be calculated as a share of the amount per measured call valued at Rs. 1.20, i.e. the highest call charge specified in the Telecommunication Tariff Order 1999;
 - this implies that for domestic long distance calls the payment should be Rs. 0.48 per measured call, and for international calls it should be Rs. 0.66 per measured call;
 - there is no specific reference in the Schedule to the revenue sharing arrangement between DOT and VSNL.
32. Schedule II specifies revenue sharing arrangements for calls made by subscribers of cellular mobile service providers. For these calls too, the revenue sharing arrangements remain essentially the same as prevailing earlier. The main change is that instead of a call charge of Rs. 1.40 per measured call used earlier, now it will be Rs. 1.20 per measured call.
33. The second consultation paper had raised a question of whether, similar to basic service providers, cellular mobile service providers should get a share of the long distance call revenue. Cellular mobile service providers had been in favour of such revenue sharing, but basic service providers were against it. The Authority has decided not to provide for such revenue sharing. An important reason for this decision is that while basic service providers have an access deficit to make up from long distance and international call charges, the situation regarding cellular mobile sector is different. For the latter, profitability has been built into the specified tariffs that are based on “median” cost estimate (and not on a lower estimate based on costs of an efficient service provider). Rentals cover capital costs and half of the license fee (for service providers in the metro area). The other half of the license fee, operational costs and a profit margin is taken into account in the calculation of the air time charge of Rs. 6 per minute. Moreover, tariff forbearance has been specified for supplementary services, which also provide a basis for substantial revenues, and tariff flexibility has been offered for cellular mobile tariffs for, *inter alia*, long distance calls made within the circle to other subscribers of the cellular mobile service provider. There does not, therefore, seem to be a basis at present to provide for revenue sharing between cellular mobile and basic service providers for long distance calls made from cellular mobile.
34. Revenue sharing arrangements relevant to cellular mobile will change with implementation of calling party pays tariff regime. Implementation of access/carriage charge regime will also imply a change in such a regime.

E. CERTAIN OTHER FEATURES

35. The Regulation includes, similar to the Telecommunication Tariff Order 1999, a reporting requirement and the possibility for the Authority to review and alter any interconnection charge or revenue sharing arrangement, whether specified by the Authority or those agreed mutually among interconnection seeker and provider.

36. Similarly, as with the Telecommunication Tariff Order 1999, the Regulation states that in matters addressed by it, the Regulation's provisions over-ride those of the license or interconnection charges and revenue sharing arrangements specified by originating, transit or terminating service providers.
37. As mentioned above, the Regulation addresses on interconnection charges and revenue sharing arrangements with regard to interconnection. Other rules and regulations pertaining to interconnection have either been specified elsewhere by the Authority, or will be addressed by other Regulations/Orders of the Authority. These include aspects such as agreement on points of interconnection, technical feasibility of providing interconnection, and the quality of interconnection services.

By Order

HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Adviser

[No. Advt.-3/4/Exty/142/99]

